

सीएम-आपदा राहत

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद आपदा प्रभावितों की मदद कर रही है और प्रभावितों तक विशेष राहत पैकेज पहुंचाया जा रहा है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कुछ वर्षों में बादल फटने व पलैश फलड की घटनाएं बढ़ रही हैं और जलवायु परिवर्तन को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा आपदा पर राजनीति कर रही है और विधानसभा में आपदा पर लाई गई चर्चा के जवाब के समय विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उन्होंने केन्द्र सरकार से हिमाचल को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी दोहराई।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पिछले अढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में वे केन्द्र सरकार से 3 हजार 9 सौ 52 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए ला चुके हैं और इसके माध्यम से विभाग में तेजी से विकास परियोजनाएं चल रही हैं। शिमला ग्रामीण क्षेत्र की डोमैहर, हिमरी व ओगली पंचायत में आज उन्होंने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में जनसुनवाई की और अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि डोमैहर पंचायत में 8 करोड़ 16 लाख रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं और सुन्नी में एस.डी.एम. कार्यालय खोलने की लोगों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि जलोग में दूध एकत्रीकरण केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

राजेश धर्माणी

तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि कृषि के प्राकृतिक उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का अग्रणी राज्य बन गया है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं क्षेत्र के औहर बीज गुणन फार्म में आज प्राकृतिक खेती पर आयोजित एक किसान गोष्ठी में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उगाए गए गेहूं, मक्का और हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय

किया है। राजेश धर्माणी ने कृषि, बागवानी, पशुपालन, रेशम और मत्स्य विभागों से समन्वय के साथ काम करने को कहा ताकि मिश्रित प्रयासों से किसानों व बागवानों को लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि औहर में 53 करोड़ रूपए की लागत से पर्यटन विकास निगम का केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

पौधरोपण

प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने समाज के सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करने का आह्वान किया है। उन्होंने आज शिमला ज़िले के नालदेहरा में पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और देवदार का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे।
